Pariksha Saathi — दैनिक करंट अफेयर्स

19 अक्टूबर 2026 • हिंदी

SSC CGL • CHSL • MTS • IBPS PO/Clerk • SBI PO/Clerk • RRB — 9 खबरें + 5 प्रश्न • स्रोत: PIB (सभी खबरें आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों से)

1 पंप भंडारण पर PIB पृष्ठभूमि रिपोर्ट: 7.43 गीगावाट चालू, 345.38 गीगावाट संभावित क्षमता चिह्नित, 2035-36 तक 100.81 गीगावाट की योजना

PIB backgrounder on pumped storage: 7.43 GW operational, 345.38 GW potential identified, 100.81 GW planned by 2035-36

Banking • SSC • General

19 अक्टूबर 2026 की PIB पृष्ठभूमि रिपोर्ट पंप भंडारण जलविद्युत को समझाती है, जिसे अक्सर 'जल बैटरी' कहा जाता है: अतिरिक्त बिजली से पानी निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है, और माँग बढ़ने पर संग्रहित पानी टर्बाइनों से छोड़कर बिजली बनाई जाती है; इससे वह दीर्घ-अवधि भंडारण मिलता है जिसकी ज़रूरत अधिक सौर और पवन ऊर्जा वाले ग्रिड को होती है। भारत में 10 परियोजनाओं में 7.43 गीगावाट पंप भंडारण क्षमता चालू है, 11 परियोजनाओं में 15.87 गीगावाट निर्माणाधीन या कार्यान्वयनाधीन है, और 8 परियोजनाओं की 10.40 गीगावाट क्षमता को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की सहमति या मूल्यांकन मिल चुका है। देश में 345.38 गीगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 320 परियोजनाएँ चिह्नित हैं, जिनमें पश्चिमी क्षेत्र (129.72 गीगावाट) और महाराष्ट्र (67.36 गीगावाट) आगे हैं, और CEA ने 2035-36 तक 100.81 गीगावाट चालू करने की योजना बनाई है, जिससे कुल क्षमता 105.56 गीगावाट हो जाएगी। IRENA के हवाले से रिपोर्ट कहती है कि स्थापित पंप भंडारण क्षमता में भारत चीन, जापान और अमेरिका के बाद दुनिया में चौथे स्थान पर है। सहायक उपायों में विद्युत मंत्रालय के अप्रैल 2023 के दिशानिर्देश, 30 जून 2028 तक आवंटित परियोजनाओं को 25 वर्षों तक अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पर सहमति की समय-सीमा 90 से घटाकर 50 दिन करना शामिल है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2324992

2 भारत पहली बार नई दिल्ली में 26-28 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय विधिक माप-विज्ञान समिति (CIML) की 61वीं बैठक की मेज़बानी करेगा

India to host the 61st meeting of the International Committee of Legal Metrology (CIML) for the first time, in New Delhi on 26-28 October

SSC • General

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 19 अक्टूबर को बताया कि भारत पहली बार 26 से 28 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय विधिक माप-विज्ञान समिति (CIML) की 61वीं बैठक की मेज़बानी करेगा, जिसका आयोजन उपभोक्ता मामले विभाग अंतरराष्ट्रीय विधिक माप-विज्ञान संगठन (OIML) के साथ मिलकर कर रहा है। इसमें 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों और विधिक माप-विज्ञान विशेषज्ञों के भाग लेने की उम्मीद है। 26 अक्टूबर को 'विधिक माप-विज्ञान में विकास' (Evolutions in Legal Metrology) पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी और 27 अक्टूबर को OIML रणनीति कार्यशाला होगी, और CIML सदस्य अंतरराष्ट्रीय अनुशंसाओं, OIML प्रमाणन प्रणाली (OIML-CS), डिजिटल परिवर्तन और क्षमता-निर्माण पर विचार करेंगे। CIML, OIML के तकनीकी और प्रशासनिक कामकाज का मार्गदर्शन करने वाला प्रमुख निर्णय-निर्माता निकाय है। CIML की 60वीं बैठक 13 और 15 अक्टूबर 2025 को पेरिस में हुई थी, जिसमें 55 सदस्य देश उपस्थित या प्रतिनिधित्व में थे।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2324997

3 MoES के सभी दस अनुसंधान संस्थान पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में PhD के लिए AcSIR संबद्ध अनुसंधान संस्थान बने

All ten MoES research institutes become AcSIR Associated Research Institutes for PhD programmes in earth system sciences

SSC • General

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने 19 अक्टूबर को बताया कि उसने और वैज्ञानिक एवं नवाचार अनुसंधान अकादमी (AcSIR) ने 13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के पृथ्वी भवन में एक समझौता ज्ञापन (MoU) की घोषणा की, जिसके तहत MoES के सभी दस अनुसंधान संस्थानों को AcSIR संबद्ध अनुसंधान संस्थान (AcSIR-ARI) की मान्यता मिली है। 21 अगस्त 2026 को निष्पादित इस MoU पर MoES की ओर से मिशन निदेशक (मिशन मौसम) डॉ. प्रवीण कुमार डी. और AcSIR के निदेशक प्रो. मनोज कुमार धर ने हस्ताक्षर किए, और इसकी घोषणा MoES सचिव डॉ. श्रीनिवास कुमार तुम्मला की उपस्थिति में हुई। AcSIR के PhD कार्यक्रम में चुने गए छात्र MoES संस्थानों में AcSIR संकाय के रूप में मान्य MoES वैज्ञानिकों की देखरेख में शोध करेंगे, और डिग्री AcSIR देगा, जिसके प्रमाण-पत्र पर मेज़बान संस्थान का नाम होगा। क्षेत्रों में मौसम पूर्वानुमान और जलवायु सेवाएँ, ध्रुवीय और क्रायोस्फ़ीयर अनुसंधान, समुद्री अवलोकन और समुद्री रोबोटिक्स, गहरे समुद्र में खनन और विलवणीकरण, भूकंप विज्ञान तथा पृथ्वी विज्ञान में AI/ML शामिल हैं; सभी दस संस्थान AcSIR के नवीनतम PhD नामांकन चक्र में भाग ले रहे हैं, और शोध से बनी बौद्धिक संपदा में छात्र को आविष्कारक के रूप में श्रेय मिलेगा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2324987

4 मत्स्यपालन सचिव ने पिथौरागढ़ शीतजल मत्स्य क्लस्टर की समीक्षा की: ट्राउट उत्पादन लगभग 5,000 मीट्रिक टन, PMMSY के तहत पर्वतीय राज्यों में 2,299 करोड़ रुपये का निवेश

Fisheries Secretary reviews Pithoragarh coldwater fisheries cluster: trout output near 5,000 MT, Rs 2,299 crore invested in hill states under PMMSY

SSC • General

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार मत्स्यपालन सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने 19 अक्टूबर 2026 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शीतजल मत्स्य क्लस्टर की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ट्राउट किसान, राज्य के अधिकारी, ICAR-DCFR भीमताल, नाबार्ड, NFDB और MPEDA शामिल हुए। सरकार ने पिथौरागढ़ (उत्तराखंड), कुल्लू (हिमाचल प्रदेश), अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर) और कारगिल (लद्दाख) में शीतजल मत्स्य क्लस्टर अधिसूचित किए हैं; भारत की शीतजल मत्स्यपालन छह पर्वतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्रित है, जिनमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत पर्वतीय राज्यों में 2,299 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है और 5,600 से अधिक रेसवे, 54 हैचरी, 293 शीतगृह और 260 फ़ीड मिलें स्वीकृत हुई हैं; एक दशक में ट्राउट उत्पादन छह गुना बढ़कर लगभग 5,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो गया है, और उत्तराखंड ने जून 2026 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय निर्यात, नेपाल को 5 मीट्रिक टन ट्राउट, किया। उत्तराखंड में पिछले छह वर्षों में 317 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, और 2.10 करोड़ रुपये मूल्य की 45 मीट्रिक टन से अधिक ट्राउट ITBP की चौकियों को आपूर्ति की जा चुकी है। चर्चा में आई कमियों में बीज (40 लाख की माँग के मुक़ाबले 15 लाख फ़िंगरलिंग का उत्पादन) और उत्पादकता (1,000 किलो की क्षमता के मुक़ाबले प्रति रेसवे 250 किलो) शामिल हैं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2325058

5 CCPA ने विस्फोटकों की ऑनलाइन बिक्री पर कार्रवाई की: 7 प्लेटफ़ॉर्म से 3,940 विक्रेता और लिस्टिंग हटीं, Dial4Trade और ExportersIndia पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना

CCPA acts against online sale of explosives: 3,940 sellers and listings removed from 7 platforms, Rs 10 lakh penalties on Dial4Trade and ExportersIndia

Banking • SSC • General

उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने 19 अक्टूबर 2026 को बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के तहत, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के साथ पढ़ते हुए, अमोनियम नाइट्रेट, बारूद, पिक्रिक अम्ल और PETN जैसे विनियमित विस्फोटक पदार्थों की अनधिकृत ऑनलाइन लिस्टिंग, विज्ञापन और बिक्री पर कार्रवाई की है। सात प्लेटफ़ॉर्म इसके दायरे में आए: IndiaMART, TradeIndia, Dial4Trade, Justdial, Sigma-Aldrich India, ExportersIndia और Ibuychemikals; कुल 3,940 विक्रेता और लिस्टिंग प्रविष्टियाँ, जिनमें IndiaMART की 3,092 शामिल हैं, हटा दी गई हैं। CCPA ने Dial4Trade पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसकी अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने 9 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के बाद ख़ारिज कर दी, और ExportersIndia पर 10-10 लाख रुपये के दो जुर्माने लगाए, जिनकी अपीलों पर सुनवाई होनी बाक़ी है। IndiaMART और Justdial की जाँच पूरी हो चुकी है, और Justdial की अंतिम सुनवाई 23 अक्टूबर 2026 को होगी। ऐसे पदार्थ बेचने के लिए लाइसेंस ज़रूरी है, और प्लेटफ़ॉर्म से अपेक्षा है कि वे विक्रेताओं के PESO लाइसेंस का विवरण दिखाएँ और ख़रीदारों का सत्यापन करें; विस्फोटकों की किसी भी ऑनलाइन बिक्री की शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर की जा सकती है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2325128

6 शिवराज सिंह चौहान ने उन्नत एग्री वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया: PM-KISAN, एग्रीस्टैक और PMFBY के लिए मोबाइल पर एक ही खिड़की, किसानों के लिए KVK से प्रशिक्षण

Shivraj Singh Chouhan launches upgraded Agri Welfare Portal: one mobile-friendly window to PM-KISAN, AgriStack and PMFBY, with KVK training for farmers

SSC • General

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 अक्टूबर 2026 को उन्नत एग्री वेलफेयर पोर्टल (Agri Welfare Portal) का औपचारिक शुभारंभ किया। इस पोर्टल का उद्देश्य किसानों को सरकारी दफ़्तरों के चक्कर लगाए बिना और बिचौलियों के बिना अपने मोबाइल फ़ोन पर सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और कृषि संबंधी जानकारी तक सीधी पहुँच देना है, और यह PM-KISAN, एग्रीस्टैक (AgriStack) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित प्रमुख पहलों के लिए सिंगल-विंडो गेटवे का काम करेगा। इसमें ऑनलाइन पात्रता जाँच और सीधे आवेदन की सुविधा है, वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से भेजी जाएगी, और मौसम, वैज्ञानिक खेती के तरीक़ों, बीज और उर्वरक की उपलब्धता तथा बाज़ार भावों की जानकारी मिलेगी। यह साधारण स्मार्टफ़ोन और कमज़ोर इंटरनेट कनेक्शन पर भी चलने के लिए बनाया गया है, स्क्रीन रीडर का समर्थन करता है, और इसे MeitY के डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल 3.0 और भारत सरकार की वेबसाइटों के दिशानिर्देश (GIGW) 3.0 के अनुरूप विकसित किया गया है। यह किसान उत्पादक संगठनों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, कृषि वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप को भी एक साझा मंच पर लाएगा, और किसानों को इसका उपयोग सिखाने के लिए देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। शुभारंभ के समय कृषि एवं किसान कल्याण सचिव अतीश चंद्रा और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अधिकारी मौजूद थे।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2325129

7 भारत–न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू: सभी भारतीय वस्तुओं को शुल्क-मुक्त पहुँच, 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता

India–New Zealand FTA enters into force on 20 October 2026: duty-free access for all Indian goods, USD 20 billion investment commitment

SSC • Banking • General

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूज़ीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने 19 अक्टूबर 2026 को एक वर्चुअल सम्मेलन में घोषणा की कि भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर 2026, विजय दशमी, से लागू होगा। न्यूज़ीलैंड ने भारतीय निर्यात से जुड़ी सभी टैरिफ़ लाइनों पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है, जिससे 10% तक के अधिकतम शुल्क हट गए हैं, और अब तक के किसी भी व्यापार समझौते में अपनी सबसे अच्छी सेवा-पेशकश की है: लगभग 118 क्षेत्रों में बाज़ार पहुँच और लगभग 139 उप-क्षेत्रों में सर्वाधिक-अनुकूल-राष्ट्र (MFN) प्रतिबद्धताएँ, साथ ही पहली बार आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष पद्धतियों सहित स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं में विशेष पहुँच। भारतीय पेशेवरों को हर वर्ष 5,000 अस्थायी रोज़गार प्रवेश वीज़ा और 1,000 वर्किंग हॉलिडे वीज़ा का कोटा मिलेगा; भारतीय छात्रों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, और STEM स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों को पढ़ाई के बाद तीन वर्ष तक तथा डॉक्टरेट शोधार्थियों को चार वर्ष तक काम करने का अधिकार मिलेगा। न्यूज़ीलैंड ने भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता जताई है, और कृषि उत्पादकता साझेदारी के तहत कीवी फल, सेब और शहद के लिए कार्य योजनाएँ और उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे, जिनमें कीवी फल के पहले चरण के स्थल फ़ुत्सेरो (नागालैंड) और मगरा (उत्तराखंड) हैं। डेयरी, चीनी, खाद्य तेल और प्रमुख कृषि उत्पाद रियायतों से बाहर रहेंगे। वार्ता 16 मार्च 2025 से 22 दिसंबर 2025 तक चली और समझौते पर 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षर हुए; इस अवसर पर भारत से न्यूज़ीलैंड को पहली बार किसी JCB मशीन के निर्यात को हरी झंडी दिखाई गई।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2325235

8 भारत–ऑस्ट्रेलिया का पाँचवाँ सैन्य अभ्यास AUSTRAHIND 2026 तिरुवनंतपुरम में शुरू, पहली बार न्यूज़ीलैंड का पर्यवेक्षक दल शामिल

Fifth India–Australia exercise AUSTRAHIND 2026 begins at Thiruvananthapuram, with a New Zealand observer delegation for the first time

SSC • General

रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत–ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास AUSTRAHIND 2026 का पाँचवाँ संस्करण 19 अक्टूबर 2026 को फ़ॉरेन ट्रेनिंग नोड, तिरुवनंतपुरम, केरल में शुरू हुआ; यह 01 नवंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के लगभग 120-120 कर्मी भाग ले रहे हैं। भारतीय दल में गढ़वाल राइफ़ल्स के जवान और अन्य शाखाओं व सेवाओं के कर्मी हैं, और ऑस्ट्रेलियाई दल में 13 ब्रिगेड के सैनिक। अभ्यास का विषय है 'संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अध्याय VII के तहत द्वीप और तटीय वातावरण में संयुक्त उप-पारंपरिक अभियान', जिसमें संयुक्त योजना, सामरिक ड्रिल और तटीय व द्वीपीय अभियानों, निगरानी और टोही, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत का प्रशिक्षण शामिल है, हवाई और समुद्री आयामों सहित। पहली बार न्यूज़ीलैंड का एक पर्यवेक्षक दल भी इसमें भाग ले रहा है। चौथा संस्करण 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक इरविन बैरक्स, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2325246

9 वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक, 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में

Financial inclusion saturation campaign from 21 October to 31 December 2026 across 2.70 lakh gram panchayats and urban local bodies

Banking • SSC • General

वित्त मंत्रालय ने 19 अक्टूबर 2026 को बताया कि वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर वित्तीय समावेशन योजनाओं और अन्य प्रमुख कार्यों की संतृप्ति के लिए 21.10.2026 से 31.12.2026 तक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगा, जिसमें 2.70 लाख ग्राम पंचायतें और शहरी स्थानीय निकाय शामिल होंगे। बैंक शिविर लगाकर PMJJBY, PMSBY और अटल पेंशन योजना में नामांकन और PMJJBY व PMSBY में आधार सीडिंग; PMJDY खाते खोलना और मौजूदा PMJDY व अन्य बचत खातों का री-KYC; जहाँ लंबित हो वहाँ C-KYC आईडी बनाना और नामांकन (नॉमिनेशन) अद्यतन करना; वित्तीय समावेशन योजनाओं, डिजिटल धोखाधड़ी और लावारिस वित्तीय परिसंपत्तियों पर 'आपकी पूँजी, आपका अधिकार' के बारे में जागरूकता सत्र; पात्र PM-किसान लाभार्थियों की संतृप्ति के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन; और आगामी रबी मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन करेंगे। 19 अक्टूबर को संयुक्त सचिव (वित्तीय समावेशन), DFS की अध्यक्षता में बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन और SLBC के साथ तैयारी बैठक हुई, और प्रगति की निगरानी राज्य प्रशासन, बैंक और DFS करेंगे।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2325230

आज का अभ्यास — 5 प्रश्न

प्र.1 20 अक्टूबर 2026 से लागू भारत–न्यूज़ीलैंड FTA के तहत भारतीय पेशेवरों को हर वर्ष कितने अस्थायी रोज़गार प्रवेश वीज़ा उपलब्ध होंगे?

(A) 2,500
(B) 1,000
(C) 5,000
(D) 10,000

प्र.2 13 अक्टूबर 2026 को घोषित MoES-AcSIR समझौते के तहत MoES के कितने अनुसंधान संस्थानों को AcSIR संबद्ध अनुसंधान संस्थान की मान्यता मिली है?

(A) सभी दस
(B) सात
(C) पाँच
(D) बारह

प्र.3 केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 अक्टूबर 2026 को PM-KISAN, एग्रीस्टैक और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए सिंगल-विंडो गेटवे के रूप में किस पोर्टल का उन्नत संस्करण लॉन्च किया?

(A) फ़ार्मर्स पोर्टल
(B) किसान सुविधा पोर्टल
(C) ई-नाम पोर्टल
(D) एग्री वेलफेयर पोर्टल

प्र.4 20 अक्टूबर 2026 की PIB पृष्ठभूमि रिपोर्ट के अनुसार 4 जुलाई 2026 को शुरू हुए उड़ान के अगले चरण का कुल परिव्यय कितना है?

(A) 10,043 करोड़ रुपये
(B) 5,091 करोड़ रुपये
(C) 12,159 करोड़ रुपये
(D) 28,840 करोड़ रुपये

प्र.5 19 अक्टूबर 2026 की PIB पृष्ठभूमि रिपोर्ट के अनुसार स्थापित पंप भंडारण क्षमता में भारत विश्व में किस स्थान पर है?

(A) चौथे
(B) दसवें
(C) पहले
(D) दूसरे

उत्तर: 1-(C) 2-(A) 3-(D) 4-(D) 5-(A)

रोज़ सुबह 7 बजे यही PDF Telegram पर: t.me/parikshasaathiapp — चैनल से जुड़ें और दोस्तों को भेजें

रोज़ का PDF: parikshasaathi.com/daily-pdf — सभी संस्करण: parikshasaathi.com/downloads/

वेबसाइट: parikshasaathi.com (हिंदी + English में 248 पाठ, रोज़ का करंट अफेयर्स, परीक्षा नोटिस)

ऐप: Pariksha Saathi — Free, Offline, SSC/Bank की पूरी तैयारी। प्रकाशक: Mahesh Srivastava, Founder. सामग्री आधिकारिक विज्ञप्तियों से AI की सहायता से तैयार; किसी विषय-विशेषज्ञ संपादक द्वारा समीक्षित नहीं। ग़लती दिखे तो parikshasaathi.com/contact/ पर बताएँ।